[श्री जैनुल बशर]

भीतरी भाग हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वहां मिशनरीज के जरिये कुछ आतंकवादी कार्यवाहियां शुरू किये जाने की योजना बना रहा है। यह रहस्योद्घाटन उन्होंने एक किताब में किया है बहुत ही सनसनीखेज तरीके से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को इस तरह की गतिविधियों का पता ही न हो? मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी को सी०आई०ए० की ऐसी गतिविधियों का पता है कि नहीं? और उससे निपटने के लिए क्या कार्यवाही आप कर रहे हैं?

पाकिस्तान की तरफ एक इशारा किया गया है एक बात समझना गलती होगी, पाकिस्तान 1971 की हार को अभी भूला नहीं है और स्थिति बिल्कुल वैसी ही सामने आ रही है जैसी तब पैदा हो गई थी। पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठा सकता है, और पंजाब पाकिस्तान की सरहद पर है, उनकी सभ्यता, भाषा, शक्लें, खाने-पीने का तरीका मिलता जुलता है। पंजाब पहले एक ही था, वहां से ट्रेन्ड लोगों का इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से। ठीक है बौर्डर सील कर दिये गये हैं काश्मीर से लेकर गुजरात तक। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लूपहोल्स रह जाते हैं और वहीं से ऐसे लोग आते हैं। तो मंत्री जी बताएंगे कि क्या कोई पाकिस्तानी हाथ होने का भी उनको पता चला है? क्योंकि पाकिस्तान के प्रैस तो आजकल पंजाब की खबरों से भरे पड़े हैं। वह उग्रवादियों की तारीफ में लेख लिख रहे हैं और एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि हिन्दुस्तान टुकड़े-टुकड़े हो रहा है। और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। और जैसे-जैसे जियाउलहक की गद्दी डोल रही है वैसे-वैसे पंजाब के मामले पर हवा दी जा रही है। उनके राजनीतिक मन्सूबे हैं नजदीक के और दूर के भी। तो गृह मंत्री जी को इस बारे में चौकन्ना रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी: जहां तक अंग्रेजी समाचार-पत्र में जो खबर निकली है उसका आर०ए०डबलू द्वारा वैरीफिकेशन किया जा रहा है और उसकी सच्चाई का पता लगाया जा रहा है।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि सी० आर०पी०एफ० को अमृतसर से हटा दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। उसका गोल्डन टैम्पिल के इलाके में कुछ रीशफलिंग किया गया है और बी०एस०एफ० को आगे को पंक्ति में किया गया है। सी०आर०पी०एफ० और बी०एस०एफ० की और बटालियनें पंजाब में भेजी गई हैं, और आतंकवादियों तथा उग्रवादियों का पीछा हर जगह तेजी से किया जा रहा है।

यह बात सही है कि फिलहाल सरकार का गोल्डन टैम्पिल में जाने का किसी प्रकार का कोई इरादा नहीं है, हालांकि हमको इस बात के लिए उकसाया जा रहा है। लेकिन उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वहां पुलिस भेजना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। इसके अलावा और जो कार्यवाही करनी चाहिए वह कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में कुछ डिमारेलाइजेशन जरूर है। उसको ठीक करने के लिए कुछ बदली भी की जा रही हैं, पुलिस की नई भर्ती भी की जा रही है। और इसके साथ ही साथ पंजाब पुलिस के आफिसर्स के तबादले भी किए गए हैं, बाहर से भी कुछ आफिसर्स और आदमी पंजाब पुलिस के साथ भेजे गये हैं।

(Interruptions)

13.10 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to take up construction of at least one hydel project in Ladakh in the Central sector

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh): The Government of India has sanctioned and taken up two giant Hydel Projects i.e. Salal and Dool Hasti in the Central sector, in the State of J and K. However, no such project has so far been taken up in the Central

Sector in the most backward area of the country, that is, Ladakh.

Great potentials exist for construction of big Hydel Projects both in Leh and Kargil districts of Ladakh which in the event of execution will be useful not only to the residents of Leh and Kargil districts but also to the entire state including the Armed Forces stationed in the area.

Two such projects, that is, Parkachik Hydel Project in Kargil and Damkhar Hydel Project in Leh are already in the detailed investigation stages.

I, therefore, urge upon the Government of India to take up for construction at least one Hydel Project either the Parkachik-Suru Hydel Project of Kargil or Damkhar Hydel Project of Leh in the Central Sector enabling the people living in the cold and desert area of Ladakh to have modern amenities.

(ii) Scarcity of drinking water in Ghazipur district of Uttar Pradesh

श्री जैनुल बशर(गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पेय जल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। गाजीपुर और मुहम्मदाबाद तहसीलों में तो स्थिति भयावह हो गई है। पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी पानी मुश्किल से मिलता है। अधिकतर अभावग्रस्त गांव में पेय जल की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि ये गांव सन् 1972 की अभावग्रस्त सूची में शामिल नहीं थे। वास्तविकता यह है कि पिछले कई वर्षों से ये गांव पेय जल से संकट-ग्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ऐसे गांवों में पेय जल व्यवस्था करने में अपने को असमर्थ बताता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के निर्देशन के अनुसार केवल उन्हीं गांवों में पेय जल की व्यवस्था की जाती है जो 1972 की अभावग्रस्त सूची में शामिल हैं।

जहां पेय-जल योजनाएं हैं भी, वहां भी बिजली न मिलने के कारण पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। जहां पेय-जल हेतु बड़े हैंड-पम्प लगाए गए हैं, वहां गांव की पूरी आबादी की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया है। अक्सर कई गांव ऐसे हैं जो कई भागों में दूर-दूर आबाद हैं, उनमें केवल एक भाग में हैंड-पाइप लगा दिया गया है, बहुत से हैंड-पाइप भी पानी देने में असमर्थ हो रहे हैं।

अभी मैं गाजीपुर से लौटा हूं। पेय जल के लिए वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि शीघ्रातिशीघ्र गाजीपुर के अभाव ग्रस्त गांवों में पेय जल की योजना लागू की जाए। जो योजना लागू है, उनमें जैनरेटरों की व्यवस्था की जाए। गाजीपुर में पेय जल की व्यवस्था हैंड पाइपों से उपयोगी नहीं होगी, वहां तत्काल नलकूपों की योजनाएं चालू की जाएं।

(iii) Scarcity of Vanaspati in the country

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 मार्च, 1984 से अप्रैल, 1984 की एक महीने की अवधि के दौरान वनस्पति के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है :—

15 मार्च, 1984	प्रति-टिन 16½ किलोग्राम	रु० 238—250
15 अप्रैल, 1984	प्रति-टिन 16½ किलोग्राम	रु० 255—260

सरकार द्वारा वनस्पति उद्योग को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12,000 रुपए प्रति-टन की व्यापारिक कीमत पर आयातित तेलों की 20 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा दिए जाने की व्यवस्था के बावजूद यह वृद्धि हुई है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में कृत्रिम अभाव दिखाकर वनस्पति की कीमतें बहुत अधिक वसूल की जा रही हैं।

दूसरी ओर वाणिज्य मंत्रालय के एक दावे के